4 किलोमीटर का क्षेत्र मध्य रेलवे के तहत पड़ता है और दूसरे वहां रेल लाइन बिछाने के लिये करीब साढे आठ करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्जफर्नांडिज) : (क) और (ख) मध्य रेलवे को मनमाड-पर्ली वैजनाथ मीटर लाइन खंड के आमान परिवर्तन के संबंध में मनमाड और अंकाई में जंक्शन प्रबंध करने हैं । मध्य रेलवे द्वारा प्रस्तुत जंक्शन प्रबंधों के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

मजदूरों के कल्याण के लिये विधान

1923. **डा० रतनाकर पाण्डेय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूरों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग ने क्या-क्या विधान बनाये हैं ;

(ख) उनके विकास के लिये क्या-क्या योजनाएं लागू की गई हैं, और

(ग) इन योजनाओं से मजदूर किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान : (क) से (ग) सरकार द्वाराअगस्त 1987 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के विचारार्थ विषयोंमें श्रमिकों के कल्याण, के लिए विधान बनाने की व्यवस्था नहीं है । तथापि, आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय "विद्यमान कानून और अन्य उपबन्धों का अध्ययन करना, जिनका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है और इन उपायों तथा साथ ही उचित प्रशासनिक उपायों और डिलीवरी सिस्टम की कारगरता का मूल्यांकन करना है ।" विद्यमान कानूनों का अध्ययन करने और विद्यमान कल्याण उपायों का मूल्यांकन करने के पश्चात, आयोग से 31 मार्च, 1991 तक अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने की आशा की जाती है ।

Decrease in dependency on agriculture

1124. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to bring down the number of agro-based people to fifty percent by decreasing the dependency on agriculture, equalising the income of agriculture sector at least to the minimum level of income of organised sector and allocation of one third of the total agricultural income for the cause of women; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) No specific proposals to reduce the population dependent on agriculture to 50 per cent, allocation of a third of the agricultural income to the cause of women and equalising the income level of agricultural sector to the minimum level of the organised sector, are under consideration. These aspects are to be generally dealt with in the Agricultural Policy Resolution, under preparation.

Capital Loans to processing units

1125. SHRI A. G. KULKARNI:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the figures of the amount disbursed either as share capital or loans to sugarcane processing units, horticulture processing units, cotton ginning and cotton spinning units in Maharashtra /Karnataka/ Haryana/ Punjab, Uttar Pradesh etc. during the last three years;

(b) whether the long standing demand of NCDC to enable to grant capital loans to processing units is conceded; and

(c) whether Government propose to give dominant roll to NCDC in rural growth?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) A Statement showing assistance disbursed by the National Cooperative Development Corporation (NCDC) to these States during the last three years for the establishment of processing units in the cooperative sector is enclosed. [*See* Appendix CLV, Annexure No. 39]

(b) NCDC has been providing term loan assistance for the small and medium sized cooperative processing units. In the case of large sized processing units like sugar factories and spinning mills, NCDC has been providing assistance for share capital participation in these units and the term loan is sanctioned by the Central Financing Institutions.

(c) NCDC has been playing an important role in the promotion and financing of rural economic activities on cooperative lines.

नेपाल में छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

1126. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में रेल मंत्री द्वारा नेपाल के प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में यह वायदा किया गया है कि भारत सदभावना के तौर पर नेपाल क्षेत्र के भीतर आने वाली छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने को तैयार है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) जून, 1990 में भारत यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ इंडिया रेलवे कंस्ट्रेक्शन कम्पनी (इरकान) और रेल इंडिया टैकनीकल और इकोनामिक सर्विसेस (राइटस) के सहयोग से रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने हेतु रेल लाइन के निर्माण की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था। हाल ही में नेपाल के प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र में रेल मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि इस प्रयोजन के लिये भारतीय शिष्ट मंडल के शीघ्र ही की यात्रा पर जाने की संभावना है।

Handing over of Travancore house to Government of Kerala

1127. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Travancore House in Delhi, which was built by the Maharaja of Travancore in 1923 on 14 acres of land, which is the property of Kerala Government, is proposed to be returned to them without delay; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The office of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Commission, who is occupying the Travancore House, has already been allotted alternative accommodation in Bikaner House barracks and Kota House hutments and the said accommodation is under repairs. As soon as the repairs work is completed and the accommodation is fit for occupation, the MRTPC will shift there and the Travancore House will be released to the Government of Kerala by the Department of Company Affairs.